बांग्लादेश ने हसीना को वापस मांगा

अंतरिम सरकार ने भारत को भेजा राजनयिक संदेश, हसीना के खिलाफ जारी है गिरफ्तारी वारंट

एजेंसियां

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक राजनयिक संदेश भेजा है। हसीना (77) बीते 5 अगस्त से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसी के साथ लगातार 16 साल से जारी उनके शासन का अंत हो गया था। ढाका स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 'मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार' के लिए हसीना और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि ढाका चाहता है कि हसीना वापस आएं और देश की न्यायायिक प्रक्रिया का सामना करें। उन्होंने कहा, 'हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए हसीना को वापस ढाका भेजा जाए।' पता चला है कि नई दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत ने एक राजनयिक नोट विदेश मंत्रालय को सौंपा है। भारत सरकार के सूत्रों ने इस पत्र के मिलने की पुष्टि की है।

सूत्रों ने कहा, 'हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बांग्लादेश उच्चायोग की ओर से आज प्रत्यर्पण अनुरोध से संबंधित एक राजनयिक नोट मिला है। इस समय हम इस मामले में इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते।' हालांकि मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री

पिछले महीने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि वह हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। उन्होंने कहा था, 'हमें हत्या के हर मामले में न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। हम भारत से कहेंगे कि वह शेख हसीना को वापस भेजे।' आठ अगस्त को पदभार ग्रहण करने वाले यूनुस ने दावा किया है कि हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और आम लोगों सहित लगभग 1,500 लोग मारे गए, जबकि 19,931 अन्य घायल हुए थे। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोपों में हसीना और उनकी सरकार में मंत्री रहे कई सहयोगियों, सलाहकारों, सैन्य और सिविल अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

इससे पहले दिन में बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना के भारत से प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, 'हमने हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। प्रक्रिया अभी जारी है।' आलम ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से ही मौजूद है और इस संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। अक्टूबर में, विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने कथित तौर पर कहा था कि यदि भारत संधि के किसी प्रावधान का हवाला देकर हसीना के प्रत्यर्पण को अस्वीकार करने का प्रयास करेगा, तो बांग्लादेश इसका कड़ा विरोध करेगा। हाल के हफ्तों में हसीना ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर 'नरसंहार' करने और अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सोमवार को जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, 'बांग्लादेश की स्थिति चिंता का विषय है, लेकिन हमारी सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय इस पर बारीकी से नजर रख रहा है और आगे भी रखेगा।'

हिंसा पर चिंता

कुछ सप्ताह पहले हसीना ने आरोप लगाया था कि उनके देश छोड़ने के बाद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार नरसंहार कर रही है और वह अल्पसंख्यकों खास कर हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत लगातार वहां हिंदुओं समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताता रहा है। पिछले कुछ महीनों में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़े हैं। दो सप्ताह पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका का दौरा किया था और उन्होंने बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित भारत की चिंताओं से अवगत कराया था।

डेढ़ साल में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां दीं : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले डेढ़ साल में युवाओं को करीब 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं और यह अपने आप में एक 'बहुत बड़ा रिकॉर्ड' है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भर्ती अभियान 'रोजगार मेला' के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मोदी ने कहा कि पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह 'मिशन मोड' में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, 'लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं।'

उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि इस 'पारदर्शी परंपरा' से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि वे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा, 'गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी के हमारे फैसले ने लाखों बेटियों के करियर को बचाया है, उनके सपनों को टूटने से रोका है। हमारी सरकार ने हर उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है।'

महिलाओं के लिए जारी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज देश महिला-नीत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।' मोदी ने कहा कि भारतीय युवाओं की क्षमता और प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और वे कई योजनाओं के केंद्र में हैं, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया या अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र में सुधार हो। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था पर होती है।

उन्होंने कहा, 'इसीलिए, नए भारत के निर्माण के लिए देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वह अब उन्हें नए विकल्प दे रही है।'

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भाषा कोई बाधा नहीं बने और इसके लिए सरकार युवाओं को 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वह ग्रामीण भारत के विकास और देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, 'रोजगार मेलों के जरिये हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।' यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। इनमें गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा शामिल हैं। रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर, 2022 को हुई थी। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बताया था कि रोजगार मेले के जरिये अब तक कई लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। **भाषा**

एक देश, एक चुनाव

समिति की पहली बैठक 8 जनवरी को

देश में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले दो विधेयकों पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी।

सूत्रों ने बताया कि भाजपा सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित विधेयकों पर संयुक्त समिति की पहली बैठक एक परिचयात्मक बैठक होने की संभावना है, जिसमें अधिकारी दोनों विधेयकों के बारे में जानकारी देंगे।

लोक सभा और विधान सभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 'संविधान संशोधन (129वां) विधेयक, 2024' और उससे जुड़े 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' पर विचार के लिए 39 सदस्यीय संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

भाजपा सांसद और पूर्व कानून राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति को बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इन विधेयकों को 17 दिसंबर को लोक सभा में पेश किया गया था। **भाषा**

जयशंकर 24 से अमेरिका की यात्रा पर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार से अमेरिका की छह दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद यह भारत की ओर से अमेरिका की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'विदेश मंत्री एस. जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे।'

एक संक्षिप्त बयान में कहा गया, 'वह प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्रियों से मिलेंगे।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे। **भाषा**

आईआईटी छात्रों को मिले नौकरी के बंपर ऑफर

संकेत कौल

सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में पिछले साल के मुकाबले इस बार प्री-प्लेसमेंट और अंतरराष्ट्रीय मार्केट समेत सभी तरह की नौकरियों के प्रस्तावों में वृद्धि हुई है। इन संस्थानों में प्लेसमेंट सीजन का पहला चरण पूरा हो चुका है। आईआईटी दिल्ली को प्री-प्लेसमेंट समेत 1,200 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। पिछले साल की समान अवधि में इस संस्थान को 1,050 प्रस्ताव आए थे। इसी प्रकार आईआईटी कानपुर में 250 कंपनियों की ओर से 1,109 छात्रों को नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं। पिछले साल पहले चरण में इस संस्थान के 989 छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव आए थे। हालांकि दोनों ही संस्थानों ने छात्रों को दिए जाने वाले औसत पैकेज और किस क्षेत्र में नौकरी मिली, इसका खुलासा नहीं किया है। खास यह कि आईआईटी के छात्रों को अलग-अलग उद्योगों से ऑफर आए हैं।

इस वर्ष आईआईटी के छात्रों को अपने यहां नौकरी देने वाली बड़ी कंपनियों में अमेरिकन एक्सप्रेस, बार्कलेज, बीसीजी, कार्स24, डॉयचे बैंक, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, इंटेल इंडिया, मीशो, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट, ओला, ऑरेकल, रिलायंस और क्वालकॉम आदि हैं।

पहले चरण में आईआईटी छात्रों को विदेशों से भी पिछले साल के मुकाबले नौकरी के अधिक प्रस्ताव आए हैं। एक आधिकारिक बयान में आईआईटी कानपुर ने कहा कि पहले चरण के प्लेसमेंट की खास बात यह रही कि छात्रों को 28 अंतरराष्ट्रीय आफर मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक हैं। आईआईटी दिल्ली को जापान, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई), ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के 15 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से 50 छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं।

प्रमुख उद्योगों में भी इस बार आईआईटी से बहुत अधिक छात्रों का चयन हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) ने बड़ी संख्या में आईआईटी से छात्रों को लिया है। सबसे ज्यादा भर्तियां बीपीसीएल ने की हैं।

आईआईटी कानपुर में स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिस के चेयरमैन प्रोफेसर राजू कुमार गुप्ता ने कहा, 'अगले साल जनवरी के मध्य से शुरू होने वाले दूसरे प्लेसमेंट चरण में अन्य चरण के प्लेसमेंट अभियान में और अधिक छात्रों की नौकरी लगने की संभावना है।'

नौकरी प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए आईआईटी दिल्ली में करियर सेवाओं की प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर नरेश वर्मा डातला ने कहा, संस्थान के लिए यह बहुत अच्छी शुरुआत है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी यही रुझान रहेगा।'

- आईआईटी दिल्ली को प्री-प्लेसमेंट समेत **1,200** से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। पिछले साल की समान अवधि में इस संस्थान को **1,050** प्रस्ताव आए थे
- आईआईटी कानपुर में **250** कंपनियों की ओर से **1,109** छात्रों को नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं। पिछले साल **989** छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव आए थे

जनसंख्या विस्फोट या आबादी में गिरावट?

पृष्ठ 1 का शेष

रीप्लेसमेंट स्तर वह आंकड़ा होता है, जितनी संतानें किसी मां को जनसंख्या स्थिर रखने के लिए चाहिए होती हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन-एफएचएस) के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल प्रजनन दर 2015-16 में भी 2.2 ही रही मगर 2019 से 2021 के दौरान घटकर 2 रह गई, जो रीप्लेसमेंट लेवल से कम है। इसका मतलब है कि देश की आबादी में अब गिरावट आएगी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) के अनुमानों से पता चलता है कि 2025 से वृद्धि दर सालाना 1 फीसदी के दायरे में रहने पर भी भारत की आबादी में गिरावट 2062 से पहले नहीं दिखेगी।

यूएन डीईएसए के अनुमान के बावजूद कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2025 में घटकर 0.9 फीसदी रह जाएगी। इसके बावजूद उस साल आबादी 1.31 करोड़ बढ़ जाएगी। यह भारत की जनसंख्या पर आधारित है जो वर्ल्डोमीटर के अनुसार 16 दिसंबर तक 1.46 अरब थी। वर्ल्डोमीटर ने चीन की जनसंख्या 1.42 अरब बताई है।

यह वृद्धि 2001 से 2011 के दशक में औसतन सालाना 1.82 करोड़ लोगों की वृद्धि के मुकाबले काफी कम होगी। इसके बावजूद 2025 में भारत की आबाद में ऑस्ट्रेलिया की लगभग आधी आबादी जितनी वृद्धि होगी जो वर्ल्डोमीटर के अनुसार 16 दिसंबर, 2024 तक 2.68 करोड़ थी।

अगर है तो जानेमाने लोग अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं।

मगर संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डेसा) का अनुमान है कि भारत की आबादी 2062 से पहले घटना शुरू नहीं होगी। हां, 2025 के बाद से इसकी वृद्धि दर घटकर 1 फीसदी के भी नीचे चली जाएगी। फिर भी हर साल देश की आबादी 1.31 करोड़ बढ़ती रहेगी।

अगर ऐसा है तो प्रमुख हस्तियां लोगों से अधिक संतानें पैदा करने के लिए क्यों कह रही हैं? इसकी दो वजहें नजर आती हैं।

पहला कारण: भारत की कुल प्रजनन दर 2019 से 2021 के बीच रीप्लेसमेंट स्तर से नीचे चली गई थी। ऐसे में चिंता है कि देश की आबादी जल्द ही बूढ़ी हो सकती है। इससे युवा आबादी वाला फायदा खत्म हो जाएगा। यूएनडेसा के मुताबिक 2024 में भारत की 68.7 फीसदी आबादी की उम्र 15 से 64 वर्ष के बीच थी। मगर कौशल और मौकों की कमी के कारण आबादी के इस पहलू का पूरा फायदा अभी तक नहीं उठाया जा सका है। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच रोजगार-याफ्ता लोगों में से करीब 20 फीसदी के पास नियमित कमाई या वेतन वाली नौकरी थीं।

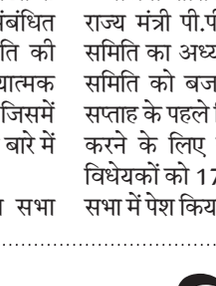

आबादी बूढ़ी होने का डर इसलिए हो रहा है कि लोग लंबी जिंदगी जी रहे हैं और कुल प्रजनन दर घट रही है। उदाहरण के लिए 2024 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 74 वर्ष हो गई यानी पुरुष औसतन 71 साल तक तथा महिलाएं औसतन 74 साल तक जी रही थीं। 2011 में पुरुषों के लिए आंकड़ा 64.6 साल और महिलाओं के लिए 67.7 साल था।

लेकिन हो सकता है कि ये आशंकाएं गलत हों। 2021 में बुजुर्गों (60 साल से अधिक उम्र के लोगों) की आबादी देश की कुल आबादी की 10.1 फीसदी थी, जो 2035 तक बढ़कर 15 फीसदी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

अहमदाबाद की एलजे यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर और विकास अर्थशास्त्री अमिताभ कुंडू कहते हैं, 'हमें घबराना नहीं चाहिए। अगले 15 साल तक हमारे सामने युवा आबादी का फायदा गंवाने का खतरा नहीं है।' उन्होंने कहा कि 2040 के बाद इसमें गिरावट आएगी, लेकिन अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

विशेषज्ञों भी मान रहे हैं कि भारत या कम से कम इसके कुछ राज्य अमीर बनने से पहले ही बूढ़े हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन कॉम्प्लेक्स चॉइसेज के प्रोफेसर और सह-संस्थापक अनिल के सूद कहते हैं कि भारत को अभी तो युवा आबादी का फायदा मिल रहा है मगर 2019 से 2021 के बीच कुल प्रजनन दर घटकर 2 रह जाने से लगने लगा है कि देश अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। यहां तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा जैसे सबसे अमीर राज्य भी 4,500 से 14,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ उच्च-मध्य आय वर्ग के निचले छोर पर आते हैं। इसलिए सूद का कहना है कि वैश्विक औसत आय के साथ ही धनी देश कहलाने की न्यूनतम आय सीमा भी बढ़ती जाएगी। इसलिए भारत को बाकी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ना होगा।

सूद यह भी कहते हैं कि भारत सालाना 10 फीसदी की दर से बढ़ा और न्यूनतम सीमा 5 फीसदी चढ़ गई तो तेलंगाना जैसे अमीर राज्य को भी धनी आय वर्ग के सबसे निचले पायदान तक पहुंचने में 25 साल लग जाएंगे। वह समझाते हैं, 'बतौर देश वहां तक पहुंचने में और भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए कुछ राज्यों में हमें करीब एक दशक में ही बड़ी संख्या में कम आय वाले बुजुर्गों के भरण-पोषण की चुनौती झेलनी होगी।'

दूसरा कारण इसके परिणाम हैं: अब राज्यों में लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की आवाजें उठने लगी हैं। विशेषकर दक्षिणी राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले कुल प्रजनन दर (टीएफआर) कम है। कुंडू कहते हैं कि भारत उन देशों में शामिल हैं, जहां वृद्ध आश्रित आबादी कम है, लेकिन, दक्षिण राज्यों में यह निर्भरता दर (कामकाजी लोगों की आबादी में वृद्धों का अनुपात) अधिक है।

उनका मानना है कि कम प्रजनन दर वाले राज्यों में इस समस्या से निपटने के लिए देश के भीतर कहीं भी रहने को खुली छूट देनी चाहिए। यद्यपि संविधानिक रूप से तो देश में प्रवासन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन हालिया वर्षों में कुछ राज्यों ने इस पर कुछ प्रतिबंध थोपे हैं।

इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा नुकसान निजी क्षेत्र को होता है। इसका उदाहरण कोविड के दौरान देखने को मिला जब हालात पटरी पर लौटे तो केरल जैसे एक छोर पर बसे राज्य से श्रमिकों को लाने के लिए बसें बिहार तक आईं।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि देश में महिला कामगारों की हिस्सेदारी दर बहुत कम है। रोजगार के अवसर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी गुणवत्ता की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कुंडू ने सुझाव दिया कि बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियों के लिए कार्यबल को कुशल और प्रशिक्षित करने की जरूरत है। साथ ही महिला कार्यबल की भागीदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यबल को कुशल बनाने पर ध्यान दिया जाए तो देश में अगले 40 वर्षों तक श्रमिकों की कमी नहीं होगी।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 (जुलाई से जून) के बीच महिला श्रमबल हिस्सेदारी दर 41.7 प्रतिशत और पुरुषों की हिस्सेदारी 78.8 प्रतिशत आंकी गई थी।

कुंडू युवा आबादी पर वृद्ध आश्रित जनसंख्या का भार कम करने के लिए 60 से अधिक उम्र के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में दोबारा प्रशिक्षित करने की जरूरत पर बल देते हैं।

सूद कहते हैं कि यदि लंबे समय के लिए इस समस्या का हल चाहते हैं तो परिवार की कमाने और बचत करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निवेश बढ़ाना होगा।

उन्होंने कहा, 'यह जानते हुए कि अभी कोविड 19 से हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं हो पाई है, असफल या बेकार परियोजनाओं में निवेश रोक कर पैसे को ऐसे संसाधन जुटाने पर खर्च करना होगा जहां भारतीयों की कमाने एवं बचत करने की क्षमता का विकास हो।' विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों ने अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी के जवाब में धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक समुदाय को अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दी, वे तथ्यों से वाकिफ नहीं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2015-16 के मुकाबले 2019-20 में सिख और जैन समुदायों को छोड़ दें तो अन्य सभी समुदायों की प्रजनन दर घटी है।

यद्यपि मुसलमानों की प्रजनन दर अभी भी प्रतिस्थापन स्तर (प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर) से अधिक है। वर्ष 2015-16 में यह 2.62 जो वर्ष 2019-21 की अवधि में घटकर 2.36 पर आ गई। अन्य सभी समुदायों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। यहां तक कि सिख और जैन समुदायों में जहां इस अवधि में प्रजनन दर बढ़ी थीं, वहीं वर्ष 2019-20 के दौरान यह क्रमशः 1.61 और 1.6 पर दर्ज की गई।

कुंडू कहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के प्रभावी होने की मौजूदा बहस निरर्थक ही है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। वह इसका कारण भी बताते हैं, 'मुसलमानों की प्रजनन दर भी कम हो रही है।' वह यह भी कहते हैं अधिक बच्चे पैदा करने की बात कोई समुदाय मानने वाला नहीं है। वह कहते हैं, 'देश बचाने के लिए कोई पुनरुत्पादन नहीं करता।'

सूद कहते हैं, 'अधिक बच्चे पैदा कर जनसांख्यिकीय लाभ लेने की जो बात समझाई जा रही है, वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि आज भी देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, जिसके पास बेहतर कमाई के अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	निविदा का नाम	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1	बैंक के नेटवर्क के व्यापक मूल्यांकन के लिए सेवा प्रदाता के चयन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध।	15 जनवरी 2025

विवरण बैंक की वेबसाइट: **www.bankofbaroda.in** पर निविदा अनुभाग, सीपीपीपी और सरकारी ई मार्केटप्लेस (GeM) पर उपलब्ध हैं।
यदि कोई परिशिष्ट होगा, GeM पोर्टल और बैंक की वेबसाइट: **www.bankofbaroda.in** के निविदा अनुभाग पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता इसे अवश्य देख लें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 24.12.2024
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
98/24-25